ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, शुक्रवार 26 सितम्बर 2025

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 2 अंक 160

भ्रष्टाचारियों आयड़ छोड़ो : वाह! कितने शानदार हैं बर्बादियों के मंजर!!! पानी उतर गया लेकिन नहीं उतरा इनके शर्म का पानी!!!



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर की लाइफ लाइन आयड़ नदी में बारिश का पानी उतर गया है। नदी के पेटे में डाली गई टनों मिट्टी, पत्थर, पौधे और घास बह चुके हैं। कहीं गड्ढे दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पर दूर से बहकर आए पत्थर बर्बादियों की कहानी कह रहे हैं। एक तरफ नदी के चैनल में पानी बह रहा है तो दूसरी तरफ विनाश की निशानियां आपको और हम सब उदयपुर शहरवासियों को परेशान कर रहे हैं। ये मंजर देख कर उन नेताओं और अफसरों पर गुस्सा आ जाता है जिन्होंने जनता के पैसों को नदी के बहाव में झोंक कर बर्बाद कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस महाविनाश में काली कमाई का भरपूर अवसर दिखाई दे रहा है। वे तैयार बैठे हैं कि कब पानी और उतरे, मानसून की विदाई के बाद बारिश के दौर थमते दिखाई दें और उनका काम शुरू हो जाए। जी हां, अब उदयपुर के कुछ महाभ्रष्ट नेताओं और महाभ्रष्ट अफसरों के गठजोड़ के लिए आयड़ नदी कमाई का जरिया बन चुका है। पिछले साल भी यही हुआ था, इस बार भी यही होना तय है। हम नदी की बर्बादी का वार्षिक शोक मनाते हैं और ये भ्रष्ट लोग इसमें हर बार भराव डालकर वार्षिक उत्सव मनाते हैं। यह देखिय, हम आयड़ के अशोक नगर वाले छोर पर हैं। यहां लगभग दो करोड़ का खर्च करके पानी के बहाव वाले नदी पेटे में पौधे लगाए गए थे। पौधारोपण वाले समारोह में सभी बड़े अफसर भी मौजूद थे। लेकिन तरस आता है उन अफसरों की पढ़ाई और नेताओं के आगे हाथ जोड़कर चरण वंदना करने वाली लाचारी पर। सबकी सोच पर पत्थर पड़ गए और सबने मिलकर आयड़ में सैंकड़ों पौधों की हत्या की पटकथा खुद अपने हाथों से लिख दी। आयड़ नदी में केवल एक दिन पानी के बहाव ने ये मंजर दिखाए हैं। अगर कभी फिर से तेज बारिश का दौर चला तो फिर से 75 करोड़ के विकास के कामों के बचे हुए अवशेषों का भी बहना तय है। खास बात ये हो रही है कि उदयपुर की जनता बार-बार गुहार कर रही है कि नदी को नदी रहने दो, नाला मत बनाओ। उसके साथ प्रयोग मत करो। मगर हमारे ढीठ नेता और भ्रष्ट अफसर किसी भी भक्ति में ऐसे तल्लीन हो गए हैं कि पब्लिक ओपीनियन की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। हमारा मानना है कि अब नेताओं के आगे हाथ जोड़कर निवेदन का वक्त बीत गया है। हर साल की आयड़ के पेटे में विकास के कामों के नाम पर धन कमाने की ये नौटंकी अब बंद होनी चाहिए। अब निवेदन नहीं, हाथों हाथ जवाब मांगने का समय आ गया है। भ्रष्टाचारियों आयड़ छोड़ो मुहिम में आप भी हिस्सेदार बनकर जिम्मेदार नागरिक होने का अहसास करवा सकते हैं। इसके लिए आपको खुली आंखों से दिख रहे आयड़ की बर्बादियों के सुबूतों को अपने कैमरे में कैद कर हमें भेजना होगा। याद रखिये, मरती हुई और मुक्ति की भीख मांगती हुई आयड़ की चीखें यदि हमने आज नहीं सुनीं तो कल प्रकृति भी हमारी चीखें नहीं सुनने वाली हैं।

मारुति इंडिया दुनिया की 8वीं सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बनी:कंपनी की मार्केट वैल्यू 5.10 लाख करोड़ पहुंची



24 न्यूज अपडेट

भारत की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अब 57.6 बिलियन डॉलर यानी 5.10 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू के साथ दुनिया की 8वीं सबसे वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है।

मारुति सुजुकी ने फोर्ड मोटर, जनरल मोटर्स और फॉक्सवैगन जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। इतना ही नहीं मारुति इंडिया ने अपनी जापानी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर (2.57 लाख करोड़) को भी मार्केट वैल्यू में मात दे दी। वहीं दुनियाभर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला 1.47 ट्रिलियन डॉलर यानी 130.38 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू के साथ टॉप पर है।

मारुति सुजुकी भारत में छोटी कारों की बिक्री में 60% से ज्यादा हिस्सेदारी रखती है। वहीं कंपनी को हाल ही में लागू हुए GST सुधारों का बड़ा फायदा मिला है। 22 सितंबर को लागू हुए नए GST नियमों ने छोटी कारों पर टैक्स कम कर दिया, जिससे मारुति की गाड़ियां और किफायती हो गईं। इसका असर यह हुआ कि कंपनी ने अपनी कई गाड़ियों की कीमतों में 1.30 लाख रुपए तक की कटौती की।

मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने बताया, 'ऑल्टो K10 में 10.6-20%, एस-प्रेसो में 12.6-24%, सेलेरियो में 8.6-17% और वैगन R में 8.7-14% की कमी की गई है। यह त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए डबल बोनांजा है।'

मानसून विदाई के बाद हिमाचल में टूरिज्म को नई रफ्तार: होटलों में 50% तक का डिस्काउंट, बस सेवाएं शुरू होने से मनाली में लौट रही रौनक



24 न्यूज अपडेट

शिमला/मनाली। हिमाचल प्रदेश में मानसून के विदा होते ही पर्यटन कारोबारियों ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बंपर डिस्काउंट की घोषणा कर दी है। शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा और चायल समेत प्रमुख हिल स्टेशनों पर होटल मालिकों ने कमरों की बुकिंग पर 50 प्रतिशत तक छूट देना शुरू कर दिया है। इस छूट के बाद अब 5 हजार रुपये का कमरा मात्र ढाई हजार और 2 हजार रुपये का कमरा केवल एक हजार रुपये में मिल रहा है। होटल व्यवसायियों का मानना है कि इससे ठप पड़ा पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा।

सड़कों और मौसम ने दी राहत

मानसून की बारिश थमने और अधिकांश सड़कें बहाल होने के बाद पिछले चार-पांच दिनों में टूरिस्ट मूवमेंट बढ़ने लगा है। शिमला के रिज और माल रोड पर चहल-पहल लौट आई है। पहाड़ी इलाकों का सुहावना मौसम और आकर्षक पैकेज पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है।

मनाली में बस सेवाएं बहाल

एक महीने बाद मनाली से लॉन्ग रूट बस सेवाएं शुरू हो गई हैं। गुरुवार को मनाली से दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर समेत अन्य शहरों के लिए बसें रवाना की गईं। अब देशभर से वॉल्वो और ऑर्डिनरी बसें भी मनाली पहुंचने लगेंगी। इसके साथ ही मनाली में रविवार तक 30% ऑक्यूपेंसी का अनुमान लगाया जा रहा है।

टूरिस्ट ऑक्यूपेंसी का हाल

शिमला व आसपास: फिलहाल 15–20% ऑक्यूपेंसी, वीकेंड पर 35% तक पहुंचने की उम्मीद। मनाली: 10% ऑक्यूपेंसी दर्ज, बस सेवाएं शुरू होने के बाद 30% तक बढ़ने का अनुमान। होटलियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी अनूप ठाकुर ने बताया कि अगले कुछ दिन तक यह छूट जारी रहेगी।

अमेरिका का बड़ा टैरिफ फैसला : ट्रम्प ने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों पर 100% टैक्स का किया ऐलान, जेनेरिक दवाओं को मिली छूट



24 न्यूज अपडेट

वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला अमेरिकी दवा उत्पादन बढ़ाने और विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। ट्रम्प ने कहा— "महामारी ने दिखा दिया कि सप्लाई चेन टूटने पर दवाइयों की भारी कमी हो सकती है। अब हम अपनी फार्मा सप्लाई चेन को सुरक्षित करेंगे।"

जेनेरिक दवाओं को छूट- भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा निर्यातक है, को राहत मिली है। जेनेरिक दवाओं को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। आंकड़ों के अनुसार, 2024 में भारत ने केवल अमेरिका को ही 8.73 अरब डॉलर (करीब 77 हजार करोड़ रुपये) की दवाइयां निर्यात की थीं, जो भारत के कुल दवा निर्यात का 31% है। अमेरिका में लिखी जाने वाली हर 10 में से 4 दवाइयां भारतीय कंपनियों की होती हैं। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से 80–90% सस्ती होती हैं, इसी कारण अमेरिकी हेल्थकेयर सिस्टम उन पर काफी हद तक निर्भर है।

भारत पहले से झेल रहा है 50% टैरिफ

गौरतलब है कि 27 अगस्त 2025 से अमेरिकी प्रशासन भारत से आने वाले कपड़े, जेम्स-ज्वेलरी, फर्नीचर और सी-फूड पर 50% टैरिफ लगा चुका है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, यह कदम भारत के 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है और डिमांड में 70% तक गिरावट आ सकती है।

अन्य उत्पादों पर भी असर

किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50% टैरिफ अपहोल्स्टर्ड (गद्देदार) फर्नीचर पर 30% टैक्स बड़े ट्रकों पर 25% टैरिफ, ताकि अमेरिकी कंपनियां जैसे पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर और मैक ट्रक्स को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके

ब्रांडेड बनाम जेनेरिक दवा

ब्रांडेड दवा: ओरिजिनल रिसर्च पर आधारित, 20 साल तक पेटेंट सुरक्षित, कीमत ऊंची। जेनेरिक दवा: पेटेंट खत्म होने के बाद बनाई जाती है, रिसर्च लागत नहीं; ब्रांडेड से 80–90% सस्ती।

भारत के लिए राहत की बात यह है कि जेनेरिक दवाएं अमेरिकी टैरिफ से बची हैं, लेकिन अन्य सेक्टरों पर लगातार बढ़ते टैक्स से भारतीय निर्यातकों की चिंता गहराई है।

सेंसेक्स 733 अंक गिरकर 80,426 पर बंद:निफ्टी भी 236 अंक लुढ़का; दवाओं पर ट्रम्प के टैरिफ से फार्मा शेयर्स 8% तक टूटे



24 न्यूज अपडेट

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 26 सितंबर को सेंसेक्स 733 अंक गिरकर 80,426 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 236 अंक की गिरावट रही, ये 24,655 के स्तर पर आ गया है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 शेयर्स गिरकर बंद हुए।

दिनभर के कारोबार के बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा, हेल्थकेयर, PSU बैंक और IT सेक्टर 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। फार्मा शेयरों में लौरस लैब्स, बायोकॉन और जायडस लाइफ के शेयर सबसे अधिक गिरे, ये सभी शेयर लगभग 8% तक की गिरावट के साथ बंद हुए।

लद्दाख हिंसा: सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक गिरफ्तार, लेह में तीसरे दिन भी कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं बंद



24 न्यूज अपडेट

लेह। लद्दाख के प्रख्यात पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया। सरकार ने उन्हें दो दिन पहले लेह में भड़की हिंसा का जिम्मेदार माना है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है, इसका आधिकारिक खुलासा अब तक नहीं हुआ है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद लेह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी है और स्कूल-कॉलेज शनिवार तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। 24 सितंबर को कैसे भड़की हिंसा 24 सितंबर को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए। सोशल मीडिया से भीड़ जुटाई गई। आंदोलनकारियों ने 23 सितंबर की रात लद्दाख बंद का आह्वान किया था और लोगों से लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की थी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। बैरिकेड्स हटाने की कोशिश में पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लेकिन भीड़ ने जवाबी कार्रवाई में तोड़फोड़ कर दी। हिंसा के दौरान बीजेपी का जिला कार्यालय जला दिया गया, वहीं CRPF की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। इस झड़प में चार युवाओं की मौत हुई, जबकि 80 लोग घायल हुए, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

वांगचुक की संस्थाओं पर शिकंजा

गिरफ्तारी से पहले ही सोनम वांगचुक की संस्थाओं पर कार्रवाई तेज हो चुकी थी— SECMOL का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द: गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया। आरोप है कि संस्था ने विदेशी फंड का दुरुपयोग किया। CBI जांच शुरू: वांगचुक की दूसरी संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख (HIAL) पर भी विदेशी चंदा कानून उल्लंघन के आरोप लगे हैं। सीबीआई ने इसके अकाउंट्स और रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। जमीन का पट्टा रद्द: सरकार ने HIAL को दी गई जमीन की लीज भी रद्द कर दी है। राजद्रोह और पुराने केस दोबारा खुले: स्थानीय पुलिस ने वांगचुक पर राजद्रोह का केस दर्ज किया, साथ ही मजदूरों को वेतन न देने की चार साल पुरानी शिकायत भी खोली गई। आयकर विभाग की नोटिस: टैक्स से संबंधित नोटिस भी भेजे गए हैं। वांगचुक ने आरोप लगाया है कि "CBI को केवल 2022 से 2024 तक के खातों की जांच करनी थी, लेकिन अब वे 2020-21 के रिकॉर्ड और शिकायत से बाहर के स्कूलों तक से दस्तावेज मांग रहे हैं। यह दमन की रणनीति है।" 6 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक लद्दाख में लगातार उभर रहे असंतोष को देखते हुए 6 अक्टूबर को दिल्ली में आंदोलनकारियों और केंद्र सरकार के बीच बैठक प्रस्तावित है। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उस समय सरकार ने वादा किया था कि हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

सेंसेक्स 556 अंक नीचे 81,160 पर बंद:निफ्टी 166 अंक गिरकर, 24,900 के नीचे आया; IT, रियल्टी और फार्मा शेयर्स आज टूटे



24 न्यूज अपडेट

शेयर बाजार में आज यानी 25 सितंबर को गिरावट है। सेंसेक्स 556 अंक गिरकर 81,160 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 166 अंक की गिरावट रही, ये 24,891 पर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और 4 में तेजी रही। आज ऑटो, IT, रियल्टी और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही।

संपादकीय : सावधानी का तकाजा

किसी भी विरोध प्रदर्शन में अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें सामने रखी जाएं, तो उसके अंजाम तक पहुंचने और सर्वमान्य हल निकलने की उम्मीद की जा सकती है। विडंबना यह है कि कई बार मुद्दे सुलगते रहते हैं और सरकार को वक्त पर उसका समाधान निकालने की जरूरत महसूस नहीं होती। वहीं लंबे वक्त तक टालमटोल या कोताही आखिरकार असंतोष की स्थिति पैदा करती है । फिर जब प्रतिक्रिया का स्वरूप अनियंत्रित और अराजक होता है, तब कई बार उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। लेह में बुधवार को हुई हिंसा इन्ही स्थितियों का नतीजा लगती है। गौरतलब है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में लोग आंदोलन पर उतरे हुए थे। पर्यावरण कार्यकर्ता खेनम वांगचुक भी दो हफ्ते से भूख हड़ताल पर थे। मगर बुधवार को यह प्रदर्शन हिंसक हो उठा और लोगों ने भाजपा कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ हुई झड़पों के दौरान कई की जान चली गई और काफी लोग घायल हो गए। सवाल है कि अपनी मांगों के साथ कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों के सामने आखिर कैसी स्थिति पैदा हुई कि उन्होंने हिंसक रास्ता अख्तियार कर लिया। पिछले कई दिनों से वहां जैसे शांतिपूर्ण हालात थे, उसमें अराजकता को अचानक उपजी किसी स्थिति का नतीजा मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। खासतौर पर जब पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने का सवाल नया नहीं हो। इसके अलावा, लेह और करगिल के लिए अलग- अलग लोकसभा सीटें तय करने और रोजगार में आरक्षण की मांग भी अहम मुद्दे हैं। दरअसल, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार की ओर यह आश्वासन दिया गया था कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस बात को करीब पांच वर्ष हो गए, लेकिन अब भी इस पर स्थानीय समूही लाख एपेक्स बाडी और करगिल लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ सिर्फ बातचीत ही चल रही है। आखिर केंद्र सरकार की घोषणाओं के समांतर लद्दाख के लोगों की स्पष्ट मांगों के बावजूद सबसे संवेदनशील और जरूरी मुद्दों पर बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने को लेकर सहमति बनाने को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई ? सच यह है कि जब प्रमुख मांगों को पूरा करने या समस्या का सर्वमान्य हल निकालने को लेकर कोताही बरती जाती है और टालमटोल किया जाता है, तो उससे जुड़े अन्य मुद्दे भी अपना असर डालने लगते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान वहां बेरोजगारी एक जटिल समस्या बन कर उभरी है। ऐसी शिकायतों ने वहां तूल पकड़ा है कि अलग-अलग बहाने बना कर स्थानीय लोगों को नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और लद्दाख को संरक्षण भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में स्थानीय लोगों, खासकर रोजगार की उम्मीद में वक्त काटते युवाओं के बीच स्वाभाविक रूप से असंतोष ने जड़ें जमाना शुरू किया। इस तरह की संवेदनशील स्थितियों से अगर समय पर नहीं निपटा जाए, तो कुछ समय बाद उन्हें संभालना मुश्किल होता है लेह में भड़की हिंसा की तुलना कुछ लोगों ने नेपाल के 'जेन- जी' से करने की कोशिश की है। बेहतर हो कि हमारे देश में अराजकता की स्थिति न उपजे । इसलिए जरूरत इस बात की है कि सरकार बिना देर किए आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों और समस्या के मूल बिंदुओं पर विचार करके एक ठोस और सर्वमान्य हल तक पहुंचे, ताकि अवांछित तत्त्वों की किसी साजिश को पांव जमाने का मौका न मिले।

भरोसे पर घात

शैक्षिक संस्थानों को आमतौर पर छात्राओं के लिए सुरक्षित परिसर माना जाता है। मगर ऐसी किसी जगह पर जब उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है और धमका कर यौन उत्पीड़न किया जाता है, तो यह एक व्यापक चिंता का विषय बनता है। दिल्ली में वसंत कुंज स्थित एक प्रबंधन संस्थान में खुद उसके संचालक ने छात्राओं से जैसा बर्ताव किया, उसने संस्थान पर भरोसे को तार-तार कर दिया है। गौरतलब है कि इस मामले का मुख्य आरोपी एक कथित स्वयंभू धर्मगुरु या बाबा है, जो संस्थान का एक संचालक भी था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छात्रवृत्ति के तहत पढ़ाई कर रही कई छात्राओं को वह काफी समय से अलग-अलग रूप से प्रताड़ित कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि इतनी संवेदनशील शिकायत पर संस्थान के अधिकारियों ने तब सुध ली, जब विवाद ने तूल पकड़ लिया। एक शर्मनाक पहलू यह भी है संस्थान की महिला कर्मी पीड़ित छात्राओं पर आरोपी की बात मानने के लिए दबाव डालती थीं । संस्थान में अपने प्रभाव के कारण आरोपी न केवल अभद्रता करता रहा, बल्कि किसी भी कार्रवाई से बचता रहा। दूसरी ओर, भविष्य तबाह कर देने की धमकी से डरी छात्राएं खामोश रहीं । इस पूरे मामले में न केवल संबंधित संस्थान, बल्कि कानून व्यवस्था की भी बड़ी नाकामी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका पुराना आपराधिक अतीत रहा हो, वह राजधानी के नामी प्रबंधन संस्थान का संचालक कैसे बन जाता है या बना रहता है ? संस्थान के परिसर से इस कथित स्वयंभू बाबा की महंगी कार भी बरामद हुई है, जिस पर राजनयिक नंबर वाली जाली प्लेट लगी थी। आरोपी की आपराधिक गतिविधियां सामने आने के बाद संस्थान ने उससे सभी संबंध जरूर समाप्त करने की बात कही, लेकिन सवाल है कि यौन उत्पीड़न संबंधी गंभीर शिकायतों के बावजूद लंबे समय तक उसे प्रबंध समिति का सदस्य और पदाधिकारी कैसे बनाए रखा गया। जबकि धोखाधड़ी और छेड़खानी के मामले उस पर पहले से दर्ज थे। कमजोर तबकों के परिवारों और उनकी बच्चियों ने एक भरोसे के साथ पढ़ाई के लिए उस संस्थान को चुना होगा। मगर वहां उनके भरोसे से जैसा खिलवाड़ किया गया, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी।

भाई साहब हैं तो मुमकिन है : चंडीगढ़ में उदयपुर से गई नई रेल सेवा का महामहिम कटारिया किया स्वागत



24 न्यूज अपडेट

चंडीगढ़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल बांसवाड़ा से रवाना की गई उदयपुर–चंडीगढ़ नई रेल सेवा आज सुबह चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री गुलाबचंद कटारिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और नई रेल की अगवानी करते हुए सभी यात्रियों का स्वागत किया। यह नई रेल सेवा क्षेत्रवासियों और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगी।

नई रेल सेवा का विवरण

उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ (गाड़ी संख्या 20989):

प्रारंभः 27 सितंबर से

प्रस्थानः प्रति बुधवार और शनिवार, शाम 16.05 बजे

चंडीगढ़ आगमनः अगले दिन सुबह 9.50 बजे

चंदेरिया स्टेशन आगमन/प्रस्थानः 18.00 / 18.02 बजे

चंडीगढ़ से उदयपुर सिटी (गाड़ी संख्या 20990):

प्रारंभः 28 सितंबर से

प्रस्थानः प्रति गुरुवार और रविवार, सुबह 11.20 बजे

उदयपुर आगमनः अगले दिन सुबह 5.25 बजे

चंदेरिया स्टेशन आगमन/प्रस्थानः शुक्रवार और सोमवार को रात 02.55 / 02.57 बजे

मुख्य पड़ाव और किराया

दोनों दिशाओं में ट्रेन रूकती हैः राणाप्रतापनगर, मावली, कपासन, चंदेरिया, भीलवाड़ा, बिजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जिंद, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट।

स्लीपरः 490

थर्ड एसीः 1,290

सेकंड एसीः 1,815

गाय बचाने के चक्कर में केमिकल ट्रेलर पलटा, नीली लपटें और धुआं देखकर लोगों में दहशत



24 न्यूज अपडेट

भीलवाड़ा। कोटा-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे NH-27 पर गुरुवार देर रात एक केमिकल पाउडर से भरा ट्रेलर पलट गया। यह हादसा एक गाय को बचाने के प्रयास के दौरान हुआ। ट्रेलर में रखा सल्फर केमिकल पाउडर सड़क पर फैल गया और अचानक नीली आग और धुआं उठने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना स्थल और वजह मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के लाडपुरा में यह घटना हुई। एसपी बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि ट्रेलर कोटा की ओर जा रहा था। लाडपुरा के अमर्तिया मंशापूर्ण महादेव के सामने एक गाय को बचाने के चक्कर में ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। पाउडर सड़क पर फैलने के बाद आग लग गई और नीला धुआं उठने लगा। हाईवे पर जाम और राहत कार्य हादसे के कारण NH-27 पर कुछ घंटे तक जाम लगा और कई किलोमीटर तक यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर मांडलगढ़ पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ख़ुशकिस्मती से ट्रेलर में मौजूद ड्राइवर सहित चार लोग आग लगने से पहले सुरक्षित बाहर निकल गए। नीली आग और उठते धुएँ को देखकर आसपास के लोग घबरा गए। सड़क पर फैलता केमिकल लिक्विड बनकर बहने लगा, जिससे स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई थी।

अतिवृष्टि से एकलिंगपुरा में 200 बीघा भूमि डूबी, किसानों पर संकट, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सरकार से राहत की मांग



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। शहर से महज 6 किलोमीटर दूर ग्राम एकलिंगपुरा में अतिवृष्टि के कारण करीब 200 बीघा कृषि भूमि पूरी तरह जलमग्न हो गई है। इस आपदा से लगभग 120 परिवारों पर आजीविका संकट खड़ा हो गया है। शुक्रवार को मेवाड़ किसान संघर्ष समिति उदयपुर के संयोजक विष्णु पटेल अपने पदाधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्र पहुंचे और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। किसानों ने बताया कि हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यहां एक सीसी रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन उचित जल निकासी व्यवस्था नहीं बनाई गई। इसी कारण भारी वर्षा के दौरान खेतों में चार से पांच फीट तक पानी भर गया। प्रभावित किसानों का कहना है कि इसका सीधा असर रबी की फसल पर पड़ेगा। वर्तमान में पशुओं के लिए हरे और सूखे चारे का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। बाजार में सूखे चारे की कीमत 10 से 15 रुपए किलो तक पहुंच गई है। किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं आया है और न ही क्षति का आकलन किया गया है। इस हालात में किसान बेरोजगार हो गए हैं। संयोजक विष्णु पटेल ने कहा कि एकलिंगपुरा अब शहरी क्षेत्र घोषित हो चुका है, इस कारण अधिकारी हाथ खड़े कर रहे हैं और किसानों की समस्याओं को अनसुना किया जा रहा है। यदि सरकार ने समय रहते राहत के ठोस कदम नहीं उठाए तो मेवाड़ किसान संघर्ष समिति आंदोलन का मार्ग अपनाने को मजबूर होगी। इस मौके पर समिति के सह-संयोजक प्रेमचंद पटेल, ग्राम पंचायत मनवाखेड़ा के पूर्व उपसरपंच शंभूलाल डांगी, एकलिंगपुरा नवयुवक मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह चुण्डावत, मंडल अध्यक्ष नारायण डांगी, माधुलाल डांगी, भेरूलाल पटेल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

तालाब में डूबने से भुआ-भतीजी की मौत



24 न्यूज अपडेट

भीलवाड़ा। करेड़ा थाना क्षेत्र के सालिया गांव में शुक्रवार को तालाब में डूबने से भुआ-भतीजी की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मवेशियों को पानी पिलाने गई थीं। जानकारी के अनुसार, तेजी कुमारी गुर्जर (भुआ) भैंसों को तालाब पर पानी पिलाने ले गई थी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरी। उसे बचाने के प्रयास में उसकी भतीजी टीना कुमारी भी तालाब में उतर गई, लेकिन दोनों डूब गईं। ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोग पहुंचे और दोनों को तालाब से बाहर निकालकर पास के अस्पताल ले गए, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर शिवपुर चौकी प्रभारी रेवत सिंह मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बलाईरी खदान चोरी प्रकरण का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार



24 न्यूज अपडेट

सलूंबर। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव के निर्देशन में जावर माइंस थाना पुलिस ने बलाईरी खदान चोरी प्रकरण का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 20 सितम्बर की रात अज्ञात लोगों ने खदान में घुसकर मशीनों के स्टटर व अन्य सामान चोरी कर लिया था। इस संबंध में 23 सितम्बर को सुरक्षा प्रभारी एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी के असिस्टेंट मैनेजर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण संख्या 119/2024 धारा 303(2) बीपीएसएम 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कृष्णपाल सिंह मीणा (40), कन्हैया लाल (45), बाबुलाल (25) और संजय (18) को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी सलूंबर जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से चोरी गया सामान बरामद करने की कार्रवाई जारी है। चारों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्यवाही की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में नारायणलाल सज्जन, हेडकांस्टेबल प्रभुलाल, कांस्टेबल जगदीश और राजकुमार शामिल थे।

रघुनाथ मंदिर परिसर स्थित ज्वेलरी शॉप में चोरी, लाखों के जेवरात ले उड़े चोर



24 न्यूज अपडेट

बांसवाड़ा। शहर के पीपली चौक स्थित रघुनाथ मंदिर परिसर के नीचे बनी एक सोने-चांदी की दुकान में देर रात चोरी की वारदात हुई। चोरों ने लोहे का दरवाजा तोड़कर दुकान में घुसते हुए लाखों के जेवरात पार कर दिए। दुकानदार विशाल सोनी के अनुसार, बदमाश करीब साढ़े तीन किलो चांदी और 13 ग्राम सोना ले गए। चोरी गए जेवरात में चांदी की हाली, नाहरमुखी, बीड़ी, कड़े, पायल, चेन, अंगूठियां और सोने के तीन टुकड़े शामिल हैं। सुबह जब दुकानदार दुकान पर पहुंचे तो दरवाजा टूटा और सामान बिखरा हुआ मिला। तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। विशाल सोनी ने बताया कि वह वर्षों से यहां व्यापार कर रहे हैं, लेकिन पहली बार इस तरह की वारदात हुई है। उनकी दुकान की लाइन में छह दुकानें हैं, किंतु चोरों ने केवल उनकी ही दुकान को निशाना बनाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें रात करीब डेढ़ बजे एक बदमाश मोटरसाइकिल से आता, ताले से छेड़छाड़ करता और थोड़ी देर बाद वापस आकर ताला तोड़कर अंदर घुसते व सामान लेकर बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। कोतवाली थानाधिकारी रूपसिंह चारण ने बताया कि फुटेज में एक बदमाश स्पष्ट नजर आ रहा है। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

बड़गांव की नवनियुक्त एसडीएम से मिला नारायण सेवा संस्थान प्रतिनिधिमंडल



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 26 सितम्बर। नारायण सेवा संस्थान के मीडिया प्रभारी विष्णु शर्मा हितैषी एवं जनसंपर्क प्रमुख भगवान प्रसाद गौड़ ने बड़गांव की नवनियुक्त उपखंड अधिकारी लतिका पालीवाल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्हें संस्थान के सेवा प्रकल्पों एवं सामाजिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही संस्थान कार्यों के अवलोकन हेतु आमंत्रण भी प्रदान किया गया। भेंट के दौरान बंसीलाल मेघवाल एवं सुरेश गर्ग भी मौजूद रहे।

समाचार भेजने के लिए हमारी मेल आई-डी पर संपर्क करें -
desk24newsupdate@gmail.com

राष्ट्रीय दशहरा मेला-2025: वंडर सीमेंट एवं नगर परिषद निम्बाहेड़ा का भव्य अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन



24 न्यूज अपडेट

निम्बाहेड़ा (कविता पारख)। राष्ट्रीय दशहरा मेला-2025 के अंतर्गत गुरुवार रात्रि को वंडर सीमेंट और नगर परिषद निम्बाहेड़ा के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। नगर परिषद परिसर स्थित मीरा रंगमंच पर हजारों श्रोताओं ने देर रात तक साहित्यिक संध्या का आनंद लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद सी.पी. जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, पूर्व विधायक अशोक नवलखा, जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर, भाजपा नगर अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी, पूर्वी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अशोक जाट, पश्चिम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह शक्तावत, वंडर सीमेंट निदेशक परमानन्द पाटीदार, आर.के. मार्बल निदेशक निर्मल दोषी, यूनिट हेड नितिन जैन और वंडर यूफोरिया अध्यक्षा अरूणा जैन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य आकर्षण रहे सुप्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास, जिन्होंने मंच का संचालन भी किया। उनकी कविताओं और गीतों ने जैसे ही मंच पर स्वर लिया, पूरा पंडाल मंत्रमुग्ध हो गया। प्रेम, राष्ट्र भक्ति और हास्य-व्यंग्य से ओत-प्रोत रचनाओं ने उपस्थित जनसमूह को देर रात तक बांधे रखा। उनके लोकप्रिय गीतों पर श्रोता झूम उठे और बीच-बीच में दर्शकों ने खड़े होकर तालियों और हूटिंग के साथ भरपूर स्वागत किया। अन्य कवियों में डॉ. भुवन मोहिनी, सुदीप भोला, दीपक पारिक, प्रवीण पांडे, साक्षी तिवारी, मोहित मौर्य, कुशाल कुलशेन्द्र, विनोद सोनी और एकाग्र शर्मा शामिल थे। हास्य, व्यंग्य, प्रेम और राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। कवि सम्मेलन में कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर, चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष रतन लाल गाडरी, प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, श्री सांवलिया जी मंदिर मण्डल ट्रस्ट अध्यक्ष जानकीदास वैष्णव, चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन, राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण हसीजा, चित्तौड़गढ़ भाजपा नगर अध्यक्ष सागर सोनी समेत आस-पास के क्षेत्रों के नागरिकों ने भाग लिया।

बरेली में 'आई लव मोहम्मद' विवाद पर बवाल, पथराव-लाठीचार्ज; मौलाना तौकीर रजा हिरासत में



24 न्यूज अपडेट

बरेली। जुमे की नमाज के बाद बरेली में 'आई लव मोहम्मद' विवाद को लेकर हालात बिगड़ गए। इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन की जिद पर उतरी भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बारादरी, प्रेमनगर और सदर कोतवाली क्षेत्र में पथराव हुआ। भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को दौड़ा-दौड़ाकर खदेड़ा। इस दौरान कई लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सड़कों पर जूते-चप्पल और ईंट-पत्थर बिखरे मिले। पुलिस ने शहर में बाजार बंद करा दिए हैं और अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है। वे इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष हैं और उन पर 2010 में बरेली दंगे भड़काने का भी आरोप है, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। 'आई लव मोहम्मद' विवाद की शुरुआत कानपुर से हुई थी, जब बारावफात जुलूस में यह बैनर लगाया गया। विरोध के बाद मामला कई शहरों में फैल गया। अब इसके जवाब में "आई लव महादेव" जैसे बैनर भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल, बरेली की सड़कों पर डीएम अविनाश सिंह, एडीजी जोन रमित शर्मा, डीआईजी अजय साहनी और एसपी रैंक के अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। शाहजहांपुर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है।

उदयपुर में जिला स्तरीय कार्यशाला: शून्य खुराक वाले बच्चों पर विशेष फोकस



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। नियमित टीकाकरण की माइक्रो प्लानिंग, समीक्षा और गुणवत्ता सुधार के लिए डब्ल्यूएचओ और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हिरणमगरी स्थित एक निजी होटल में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य उद्देश्य जिले में जीरो डोज वाले बच्चों तक टीकाकरण सुनिश्चित करना रहा। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक आदित्य ने प्रसूताओं को दी जाने वाली एएनसी सेवाओं की समीक्षा की और पीएमएसए व पीएनडी से जुड़े बिंदुओं पर जानकारी दी। एसीएमएचओ डॉ. रागिनी अग्रवाल ने परिवार नियोजन साधनों और उनकी महत्ता पर प्रकाश डाला। डब्ल्यूएचओ के सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉ. अक्षय व्यास ने जीरो डोज बच्चों के टीकाकरण के दिशा-निर्देश दिए और 12 अक्टूबर को प्रस्तावित उप-पल्स पोलियो अभियान के लिए चिकित्साधिकारियों को आमुखीकरण कराया। शहर प्रभारी एवं उपनिदेशक डॉ. कैलाश शर्मा ने संभावित प्रतिकूल प्रभाव (AEFI) और कोल्ड चेन प्रबंधन पर तकनीकी जानकारी साझा की। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. विक्रम सिंह ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के दिशा-निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉ. शंकर एच. बामनिया ने शिविरों की रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत बनाने पर बल दिया और बच्चों के जीरो डोज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। कार्यशाला में बड़गांव, भीण्डर, गिर्वा, कुराबड़, मावली और वल्लभनगर ब्लॉक के खंड मुख्य चिकित्साधिकारी एवं चिकित्साधिकारी प्रमुख भी उपस्थित रहे।

ऑपरेशन चक्रव्यूह : धरियावद व देवगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई

10 क्विंटल 73 किलो 25 ग्राम डोडाचूरा जब्त, अनुमानित कीमत 1.60 करोड़ रुपये



24 न्यूज अपडेट

जयपुर 26 सितंबर। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना धरियावद और थाना देवगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर करीब 10 क्विंटल 73 किलो 25 ग्राम अवैध डोडाचूरा सहित परिवहन में प्रयुक्त ईसूजी लोडिंग वाहन भी जब्त किया गया। जब्त डोडाचूरा की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपये आंकी गई है।

यह बड़ी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक श्री बी आदित्य के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह व पुलिस उप अधीक्षक नानालाल के मार्गदर्शन में थाना धरियावद और थाना देवगढ़ की संयुक्त टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दी।

ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत शुक्रवार को धरियावद थानाधिकारी कमलचन्द मीणा मय जाप्ते के साथ जवाहर नगर चौराहे पर सघन नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान प्रतापगढ़ की तरफ से एक बिना नम्बरी ईसूजी लोडिंग वाहन आता दिखा, जिसके पीछे तिरपाल लगा हुआ था। पुलिस टीम को संदेह होने पर रुकने का इशारा करने पर चालक वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से रोड साइड से होते हुए मुंगाणा रोड की तरफ भगा ले गया।

पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए सरकारी वाहन से ईसूजी लोडिंग वाहन का पीछा शुरू किया। पीछा करने पर चालक ने कुछ दूर जाकर ईसूजी वाहन को रोड पर ही खड़ा कर दिया और वाहन में बैठे दोनों व्यक्ति खाई में कूदकर घने जंगल में भाग गए। पुलिस जाप्ते ने उनका काफी पीछा किया, लेकिन वे जंगल का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे।

मौके पर पुलिस ने लोडिंग ईसूजी वाहन जब्त किया। पुलिस टीम ने तत्काल जब्त किए गए लोडिंग वाहन की तलाशी ली। वाहन के पीछे काले रंग के 49 कट्टे मिले। खोलने पर उनमें अवैध अफीम अधकुटा डोडाचुरा भरा पाया गया। जिसका कुल वजन 10 क्विंटल 73 किलो 25 ग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 01 करोड़ 60 लाख रुपये आंकी गई है।

डोडाचुरा और ईसूजी वाहन जब्त कर थाना धरियावद पर संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मामले का अनुसंधान, आगे की कार्रवाई और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जांच एसएचओ देवगढ़ महेन्द्र सिंह को सौंप दिया गया है।

यह सफलता थानाधिकारी धरियावद कमल चन्द मीणा की अगुवाई में की गई। जिसमें थाना धरियावद, देवगढ़ और पारसोला थानों के 16 पुलिसकर्मी शामिल थे।

एमपीयूएटी में दो दिवसीय क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रसार सलाहकार समिति रबी-2025 की बैठक संपन्न



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी), उदयपुर के अनुसंधान निदेशालय सभागार में संभाग चतुर्थ-अ की दो दिवसीय क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रसार सलाहकार समिति (रबी-2025) की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक ने की। बैठक में निदेशक अनुसंधान ने बताया कि गत वर्ष वैज्ञानिकों द्वारा कुल 49 तकनीकी अनुशंसाएं दी गईं तथा मक्का, औषधीय फसलें, मूंगफली और ज्वार की नवीन किस्में अधिसूचित की गईं, जो विश्वविद्यालय में हो रहे उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य का परिचायक है। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम के अनुरूप किस्मों का विकास तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है, ताकि जनमानस को रसायनमुक्त भोजन और पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सके। प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. आर. एल. सोनी ने कहा कि राजस्थान विभिन्न फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। आधुनिक तकनीकियों और प्राकृतिक खेती को अपनाकर उत्पादन व किसानों की आमदनी में वृद्धि संभव है। राजस्थान कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता एवं छात्र कल्याण निदेशक डॉ. मनोज महला ने राज्य में गुणवत्ता नर्सरियों की स्थापना पर जोर दिया, ताकि किसानों को श्रेष्ठ पादप सामग्री मिल सके। बैठक की शुरुआत में संयुक्त निदेशक कृषि विभाग, भीलवाड़ा श्री विनोद कुमार जैन ने रबी 2024 के दौरान वर्षा वितरण, फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादकता का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने फसलों में आई समस्याओं के समाधान और किसानों की आय बढ़ाने हेतु उन्नत बीज, फसल विविधिकरण तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक डॉ. अमित त्रिवेदी ने स्वागत भाषण देते हुए विश्वविद्यालय की विभिन्न परियोजनाओं और संभाग की कृषि जलवायु परिस्थितियों पर जानकारी दी। उन्होंने संभाग की फसलों में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। बैठक में श्री महेश चेजारा (संयुक्त निदेशक उद्यान, भीलवाड़ा), डॉ. ओ. पी. शर्मा (उपनिदेशक, चित्तौड़गढ़), श्री रमेश आमेटा (कृषि अनुसंधान अधिकारी, चित्तौड़गढ़), श्री पी. सी. वर्मा (परियोजना निदेशक, आत्मा, चित्तौड़गढ़) तथा डॉ. रविकांत शर्मा (उपनिदेशक, अनुसंधान निदेशालय, उदयपुर) सहित वैज्ञानिक और अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विभिन्न अनुसंधान व विस्तार कार्यों की समीक्षा की गई और किसानों के हित में नई सिफारिशें जारी की गईं। यह जानकारी डॉ. जी. एल. मीना, मीडिया प्रकोष्ठ एवं जनसंपर्क अधिकारी ने दी।

भीलवाड़ा में 1 करोड़ 62 लाख की अफीम डोडा-चूरा तस्करी पकड़ी, बोलेरो और क्रेटा कार जब्त



24 न्यूज अपडेट

जयपुर 25 सितंबर। चित्तौड़गढ़ जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने 93 साल के एक बुजुर्ग को बैंक से अपहरण कर उनके साथ मारपीट कर 50,000 रुपये लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने न सिर्फ दोनों लुटेरों को पकड़ा बल्कि पूरी लूटी हुई रकम और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली हैं।

एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 4 सितंबर को महेशपुरम निवासी 93 वर्षीय मनोहर सिंह चुण्डावत अपनी पेंशन निकालने के लिए एसबीआई बैंक गए थे। उन्होंने अपने खाते से 50,000 रुपये निकाले। बैंक के बाहर ही दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें बहला-फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। वे बुजुर्ग को शहर के बाहरी इलाके, ओछड़ी से महेशपुरम की ओर जाने वाली सुनसान सड़क पर ले गए।

वहां दोनों लुटेरों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की और उनके पास मौजूद सारे 50,000 रुपये छीनकर फरार हो गए। इस वारदात से बुजुर्ग को काफी चोटें आईं। पीड़ित के पोते राजेंद्र सिंह चुण्डावत ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी त्रिपाठी ने एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का सुपरविजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता और सीओ दिनेश चौधरी तथा नेतृत्व कोतवाली थानाधिकारी तुलसीराम ने किया। पुलिस ने किसी भी तरह की देरी किए बिना तुरंत जांच शुरू कर दी।

तकनीकी साक्ष्यों से ज्यादा पुलिस टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मानवीय खुफिया जानकारी पर भरोसा किया। कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने दो आरोपियों की पहचान की। ये आरोपी किशन नाथ कालबेलिया पुत्र रामलाल (26) और कैलाश नाथ कालबेलिया पुत्र अमरचंद (32) हैं, जो थाना सदर क्षेत्र के लालजी का खेड़ा के रहने वाले हैं।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके पास से लूट की गई पूरी 50,000 रुपये की राशि बरामद कर ली। इसके अलावा, वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली गईं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा बने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 61वें जन्मदिन पर संभालेंगे पदभार



24 न्यूज अपडेट

जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को आदेश जारी कर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 27 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। यह नियुक्ति राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कल्पथी राजेंद्रन श्रीराम के 27 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के कारण की गई है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसे गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाएगा। जस्टिस श्रीराम का 69 दिन का कार्यकाल न्यायमूर्ति श्रीराम ने 21 जुलाई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। उनका कार्यकाल केवल 69 दिनों का रहा क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 27 सितंबर 2025 थी। जस्टिस श्रीराम का जन्म 28 सितंबर 1963 को हुआ था और उन्हें 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद वे 27 सितंबर 2024 को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा का प्रोफाइल

जन्म: 27 सितंबर 1964, जयपुर
शिक्षा: B.Sc., LL.B.
पेशेवर शुरुआत: 30 मई 1987, राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत
विशेषज्ञता: संवैधानिक, सेवा, वाणिज्यिक, श्रम, आपराधिक, मध्यस्थता मामलों में प्रैक्टिस
राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष
जस्टिस शर्मा अपने 61वें जन्मदिन पर 27 सितंबर 2025 राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे।
न्यायिक करियर में महत्वपूर्ण तबादले
16 नवंबर 2016: राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश (वकील कोटे से)
1 जनवरी 2022: पटना हाईकोर्ट में तबादला
2023: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट स्थानांतरण (स्वास्थ्य कारणों से)
14 जुलाई 2025: पुनः राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरण
जस्टिस शर्मा की खंडपीठ राजस्थान में चर्चित SI भर्ती मामले की सुनवाई कर रही है और उन्हें कानूनी अनुसंधान के क्षेत्र में भी व्यापक अनुभव प्राप्त है।

चिरायु जोशी को पीएचडी की उपाधि

24 न्यूज अपडेट



उदयपुर। जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय ने संस्कृत विभाग के शोधार्थी चिरायु जोशी को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। शोधार्थी जोशी ने "संस्कृत वांग्मय में प्रतिबंधित शिक्षा शिक्षण एवं आधुनिक शिक्षण का तुलनात्मक अध्ययन" विषय पर अपना शोधकार्य मार्गदर्शक डॉ. नारायण सिंह राव के निर्देशन में पूर्ण किया। इस उपलब्धि पर परिवारजनों, गुरुजनों और शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। चिरायु जोशी ने सभी का धन्यवाद अर्पित किया।

डीपीएस की सूचना मांगते ही शिक्षा विभाग के उड़ गए होश, बहाने बनाकर इनकार किया तो सूचना आयुक्त ने चलाया डंडा



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट उदयपुर। डीपीएस स्कूल जमीन आवंटन पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूचना आयोग ने शिक्षा विभाग को 30 दिन में सूचना देने का आदेश दिया है। उदयपुर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत करते हुए सूचना को रोकने का भरसक प्रयास किया। डीपीएस से संबंधित फाइलों पर खुद कुंडली मार कर बैठ गए मगर राज्य सूचना आयोग में मामला जाते ही कलई खुल गई। सुनवाई में बुलाया तो कोई नहीं गया। इस पर आयोग ने तुरंत 30 दिन मे सूचना देने का आदेश दिया है। इससे अफसरों के होंश उड़े हुए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि जिस सच पर पहरा देने के लिए मिलीभगत के खेल खेल गए कहीं वे जनता के सामने नहीं आ जाएं। इस मामले से यह भी साबित हो गया कि शिक्षा विभाग के कुछ लोग केवल और केवल प्रभावशाली लोगों के लिए काम करते हैं। उनको उदयपुर जिले के आदिवासी बच्चों के हितों से कोई मतलब नहीं है। प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर वे फाइलों पर कुंडली मारकर पसर जाते हैं और सोचते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उदयपुर के डीपीएस स्कूल ने आदिवासी बच्चों के कल्याण के नाम पर जमीन ले ली मगर आदिवासी बच्चों को शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं कियां। कितने आदिवासी बच्चों को शिक्षा मिली, इसके आंकड़े ना तो शिक्षा विभाग के पास हैं ना ही यूडीए के पास। यदि हैं तो भी छिपाए जा रहे हैं क्योंकि आंकड़े सामने आते ही डीपीएस स्कूल व सोसायटी कठघरे में खड़ी हो जाती है।

आपको याद दिला दें कि भुवाणा स्थित मंगलम सोसाइटी के डीपीएस स्कूल को शहरी सुधार न्यास (यूआईटी/यूडीए) द्वारा रियायती दर पर आवंटित की गई करोड़ों की जमीन पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार जयवंत भेरविया की ओर से दायर की गई आरटीआई (सूचना का अधिकार) और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को की गई शिकायत के बाद यह मामला गहराता जा रहा है। शिक्षा विभाग से आरटीआई में पूछे गए तीन अहम सवाल वर्ष 2005 से अब तक आवंटन शर्तों के अनुसार विधवा महिलाओं के बच्चों, शहीद सैनिकों के बच्चों, विकलांग बच्चों, एससी-एसटी वर्ग एवं गरीब आदिवासी बच्चों को रियायती दर/मामूली फीस पर डीपीएस स्कूल में दिए गए एडमिशन की वर्षवार जानकारी।

गरीब आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल में बनाए गए होस्टल की सत्यापित सूचना।

डीपीएस स्कूल से संबंधित मामलों में यूडीए द्वारा शिक्षा विभाग को भेजे गए पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

इस आरटीआई के लिए दो स्तरो पर उदयपुर में जवाब नहीं दिए गए जिस पर राज्य आयोग में शिकायत की गई।

आयोग का निर्णय (दिनांक 19.09.2025) मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि पत्रावली के अवलोकन में स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी (जयवंत भेरविया) ने दिनांक 28.05.2025 को उपरोक्त तीन बिंदुओं पर सूचना चाही थी, जो अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रत्यर्थी (शिक्षा विभाग) द्वारा आयोग को कोई अपीलोत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। इसे आयोग ने प्रत्यर्थी की उदासीनता और लापरवाही माना तथा चेतावनी दी कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। अपीलार्थी के प्रति न्यायोचित व्यवहार करते हुए आयोग ने आदेश दिया कि निर्णय की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर उपलब्ध अभिलेखीय सूचना अथवा स्पष्ट विनिश्चय अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से निःशुल्क भेजा जाए। 18 साल से पालन पर सवाल, क्यों सोया है शिक्षा विभाग दस्तावेजों और जांच से यह भी सामने आया कि जमीन आवंटन के 18 साल बीत जाने के बाद भी डीपीएस स्कूल में आवंटन शर्तों की कभी गंभीरता से जांच नहीं की गई। यूडीए के पास इन एडमिशनों से जुड़ा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं और अब शिक्षा विभाग ने भी अब तक कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत, डीपीएस स्कूल को और अधिक जमीन भी आवंटित कर दी गई है।

बड़ा सवाल

अब शहर में यही चर्चा है कि क्या जिन गरीब, आदिवासी, विकलांग और शहीद सैनिकों के बच्चों के नाम पर यह जमीन कौड़ियों में दी गई थी, उन्हें वास्तव में कोई लाभ मिला? क्या शिक्षा विभाग और यूडीए की मिलीभगत ने आवंटन शर्तों और सामाजिक न्याय की मूल भावना को दरकिनार कर दिया? यह मामला अब सिर्फ जमीन और एक स्कूल का नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग की जवाबदेही, पारदर्शिता और वंचित वर्गों के हक का है। मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर के आदेश के बाद अब निगाहें शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि वह 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराता है या मामला एक बार फिर फाइलों में दबा दिया जाएगा।

2005: 'गरीबों-आदिवासियों की पढ़ाई' के नाम पर जमीन की मांग

वर्ष 2005 में मंगलम सोसायटी के चेयरमैन गोविंद अग्रवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भुवाणा में रियायती दरों पर जमीन मांगी। जबकि सच यह है कि अग्रवाल के पास पहले से ही बड़ी निजी जमीनें मौजूद थीं। पत्र में दावा किया गया कि डीपीएस फ्रेंचाइजी खोलकर यहां गरीब और आदिवासी बालक-बालिकाओं को उच्चस्तरीय शिक्षा, छात्रावास और खेल मैदान जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

सरकार ने इन झूठे दावों के आधार पर सोसायटी को 7 एकड़ (3,04,920 वर्गफीट) जमीन आवंटित की। इसमें से 2 एकड़ जमीन तो महज 25 प्रतिशत दर पर सोसायटी को सौंप दी गई। शेष जमीन भी न्यास दरों पर रियायत के साथ दी गई।

शर्तें साफ थीं लेकिन कभी निभाई नहीं गईं

लीज डीड में सोसायटी को कुछ स्पष्ट शर्तों के साथ जमीन दी गईः जमीन का उपयोग सिर्फ शिक्षा व संबंधित प्रयोजन के लिए। जमीन का किसी अन्य संस्था को हस्तांतरण पूर्णतः अवैध था। सबसे अहमः 25 फीसदी सीटें एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, शहीद सैनिकों और विधवाओं के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। इनमें 12 प्रतिशत एससी, 8 प्रतिशत एसटी और 3 प्रतिशत विकलांग छात्रों के लिए तय था। और इन वर्गों से केवल 50 फीसदी फीस ली जानी थी। इन शर्तों की पालना पूरी लीज अवधि तक करना अनिवार्य था। वास्तविकताः न एडमिशन, न पालन-सिर्फ मुनाफाखोरी गोविंद अग्रवाल और उनकी सोसायटी ने शर्तों की कभी भी पालना नहीं की। डीपीएस स्कूल में अब तक आवंटन शर्तों के मुताबिक एडमिशन नहीं दिए गए। स्कूल ने केवल आरटीई के एक्ट 2009 का सहारा लिया, जबकि यह पूरी तरह अलग विषय है। आरटीई के तहत किसी भी निजी स्कूल को 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए देनी ही होती हैं, चाहे स्कूल ने बाजार भाव पर जमीन खरीदी हो या रियायती दर पर। लेकिन मंगलम सोसायटी को मिली जमीन की शर्तें इससे अलग थीं। उन्हें अतिरिक्त 25 प्रतिशत सीटें आधी फीस पर गरीब-आदिवासी बच्चों के लिए देनी थी। यानि डीपीएस को कुल 50 प्रतिशत एडमिशन गरीब और कमजोर वर्गों के लिए सुनिश्चित करने थे। पर वास्तविकता में स्कूल ने न तो यह शर्त निभाई और न ही आधी फीस पर बच्चों को पढ़ाया।

कांग्रेस सरकार ने भी किया खेल

कांग्रेस सरकार के अंतिम दिनों में भी डीपीएस स्कूल को फायदा पहुँचाया गया। जिस एक लाख वर्गफीट जमीन पर सालों से स्कूल का कब्जा था, उसे 60 समाजों की सूची में शामिल कर आधिकारिक तौर पर सौंप दिया गया। अब तक डीपीएस को करीब 4 लाख वर्गफीट जमीन दी जा चुकी है। यह राजस्थान का शायद पहला स्कूल है जिसे भूमि आवंटन नीति 2015 को रौंदकर इतनी जमीन सौंप दी गई। पत्रकार जयवंत भैरविया की शिकायत और सरकार का आदेश वरिष्ठ पत्रकार जयवंत भेरविया ने इस घोटाले की शिकायत मुख्य सचिव सुधांशु पंत से की और जमीन निरस्त करने की मांग रखी। इस पर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने 8 अप्रैल 2025 को यूडीए को जांच रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने 9 अप्रैल को सचिव हेमेंद्र नागर की अध्यक्षता में समिति बनाई। इसमें जितेंद्र ओझा, बिंदुबाला राजावत, अभिनव शर्मा, बाबूलाल तेली, राजेंद्र सेन और सुरपाल सोलंकी शामिल थे। 17 अप्रैल को गोविंद अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया।

यूडीए की रिपोर्टः घोटाले पर पर्दा

रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि डीपीएस ने 2012-13 से 2024-25 तक आरटीई के तहत एडमिशन दिए हैं और हर साल सत्यापन हुआ है। इस आधार पर रिपोर्ट यह निष्कर्ष देती है कि शर्तों का पालन हुआ। यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आवंटन शर्तें और आर टी ई एक्ट 2009 पूरी तरह अलग विषय हैं, तो यूडीए ने क्यों दोनों को एक जैसा मान लिया? असल में यूडीए की यह टिप्पणी सीधे-सीधे गोविंद अग्रवाल को बचाने और सरकार को गुमराह करने की कोशिश है। यह केवल आरटीई की आड़ में आवंटन शर्तों की घोर अवहेलना पर पर्दा डालने जैसा है।

राज्यपाल से दूसरी बार मिली पीड़िताएं-परिवाद पर पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई, 9 महीन से विश्वविद्यालय ने नहीं दिया वेतन, न जांच ना कोई राहत!! एसएफएबी कर्मचारियों ने भी रखी समस्याएं



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। पुलिस में परिवाद दिए महीनों बीत गए, ना तो कोई सुनवाई हुई, ना किसी का फोन आया। ना हमको बुलाया ना ही कोई राहत दी। विश्वविद्यालय में भी पीड़ा बताई लेकिन 9 महीने से वेतन को तरस रहे हैं। अवकाश प्राप्त वीसी प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने प्रताड़ित किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, हमने शिकायत की मगर कहीं कोई सुनने तक को तैयार नहीं है। यहां तक कि राज्यपाल महोदय आपश्री को ज्ञापन देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही एसएफएबी के कर्मचारियों को हर महीने वेतन के लिए तरसाया जा रहा है। जान बूझकर ऐसी हड़ताल की नौबत लाई जा रही है। आखिर यह सब कब तक चलेगा। हमें न्याय कब मिलेगा। यह पीड़ा आज राजस्थान के राज्यपाल हरिभाउ किसनराव बागड़े के समक्ष मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की एसएफएबी महिला कर्मचारियों व प्रतिनिधिमंडल ने व्यक्त की। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय संविदा/एस.एफ.एस. कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने कुलाधिपति हरिभाऊ किसनराव बागड़े से मिलकर संगठन की पांच सूत्री मांगों और दोनों महिला कर्मचारीयों को न्याय दिलाने की गुहार लगाई।

अध्यक्ष नारायण लाल सालवी ने बताया कि कुलाधिपति हरिभाऊ किसनराव बागडे के उदयपुर प्रवास के दौरान संविदा/एस.एफ.एस. कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मंडल को उनसे सर्किट हाऊस में मिलने का समय दिया गया। मुलाकात के दौरान श्रीमती किरण तंवर और श्रीमती बेबी गमेती की पीड़ा को माननीय राज्यपाल महोदय ने बहुत ही इत्मीनान से सुना और श्रीमती किरण तंवर को आज ही 9 माह से बकाया वेतन को दिलाने का आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे कामचलाउ वीसी प्रोफेसर कर्नाटक से से वे आज ही इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोनों महिलाओं ने कुलाधिपति को यह भी बताया कि उनके द्वारा प्रतापनगर थाने में दिए परिवाद की अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। इसके लिए कुलाधिपति ने अधिकारियों को वस्तु स्थिति पता लगाने के लिए कहा और त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया। संगठन की पांच सूत्री मांगों के लिए उन्होंने कुलगुरु प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक से बात करके जल्दी ही समाधान करवाने के लिए कहा है। संगठन के प्रतिनिधि मंडल मै अध्यक्ष नारायण लाल सालवी, श्रीमती किरण तंवर, श्रीमती बेबी गमेती, अजय आदिवाल, हितेश आदि उपस्थित थे।

आखिर किसका है दबाव, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई

विश्वविद्यालय की दो महिला कर्मचारियों को जो एसएफएबी बोर्ड के तहत कार्यरत हैं, उनको आखिर बिना किसी लिखित आदेश के केवल मौखिक रूप से ही आदेश देते हुए वीसी प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के बंगले पर क्यों भेजा गया। उन्हें भेजने वाले, उनसे सेवाएं लेने वाली वीसी व अन्य पर कार्रवाई कब होगी। इसके लिए सुविवि में कोई भी कमेटी का अब तक गठन नहीं किया गया है। एसएफएबी कर्मचारियों ने लगातार अपनी मांग और पुलिस कार्रवाई करते हुए दबाव मगर आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। पुलिस लंबे समय से परिवाद लेकर खामोशी बैठी है। यहां तक कि दोनों को बुलाकर पूछा भी नहीं गया है कि घटना क्या हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जांच होते ही किसी ऐसे व्यक्ति के फंसने का अंदेशा हो जो बहुत बड़े जेक जरिये की वजह से उदयपुर में कार्य कर रहा है। इसका खुलासा होना चाहिए कि पुलिस पर क्या दबाव है कि परिवाद देने के बाद और एसपी के समक्ष पेश होने के बाद भी इस मामले में एक कदम भी जांच आगे नहीं गई है। जबकि खुद राज्यपाल पिछली बार व इस बार भी कह चुके हैं कि वे खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब माननीय राज्यपाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो फिर जांच किसकी, कहां व कौन कर रहा है। इसके अलावा एसएफएबी कर्मचारियों को हर महीने वेतन के लिए तरसाना भी अमानवीय हैं। इसके लिए दोषियों को भी तुरंत पहचान कर उचित पनिशमेंट मिलना चाहिए मगर सुविवि में राजनीतिक दखल, उपर तक मिलीभगत व घालमेल के चलते ऐसा नहीं हो रहा है। हर महीने वेतन के लिए एसएफएबी को तरसा कर हड़ताल के लिए उकसाया जाता है। उसके बाद जब स्ट्राइक होती है तो उन्हें उल्टा दोषी करार दिया जात है। उनका वेतन काट लिया जाता है। इसकी जांच के लिए भी कोई कमेटी नहीं बनी है। अब मामला जब राज्यपाल महोदय के पास गया है तो कुछ कार्रवाई की उम्मीद बंधी है मगर पूर्ण विश्वास अब भी कार्मिकों को नहीं है क्योंकि पिछले ज्ञापन में भी वहीं सब बातें लिखीं व कहीं गईं थी। उसके इतने दिन बाद भी कुछ क्यों नहीं हुआ????

ओसवाल सभा की बैठक : 29 को कुलदेवी मंदिर का शिलान्यास, 2 को साधारण सभा, 21 दिसम्बर को स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। ओसवाल सभा उदयपुर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र कोठारी की अध्यक्षता में ओसवाल भवन, मुखर्जी चौक में आयोजित हुई। सह सचिव मनीष नागोरी ने बताया कि बैठक में भवन के निर्माण कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर दरवाजे, खिड़कियां, फाटक और फर्नीचर बनवाने के साथ ही पुराने भवन के रंग-रोगन संबंधी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस दौरान सभी सदस्यों ने निर्माण कार्य का अवलोकन भी किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार, 29 सितम्बर को नवरात्रि के अवसर पर ओसवाल सभा परिसर में कुलदेवी ओसिया माता मंदिर के निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाएगा। वहीं, आम साधारण सभा का आयोजन रविवार, 2 नवम्बर 2025 को होगा। इस अवसर पर नवनिर्मित कार्यालय कक्ष, मुख्य द्वार, बैठक हाल एवं रेस्ट रूम का लोकार्पण भी किया जाएगा। सभा ने 21 दिसम्बर को स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें 10वीं व 12वीं कक्षा में 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं, साथ ही IAS, RAS, IPS, IIT, IIM, RJS, MBBS में चयनित तथा CA-CS पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों और राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि ओसवाल सभा के आगामी चुनाव 11 जनवरी 2026 को संपन्न होंगे। बैठक में उपाध्यक्ष डॉ. तुक्तक भाणावत, सचिव आनंदीलाल बंबोरिया, कोषाध्यक्ष फतेह लाल मेहता, भंडार संरक्षक फतेह लाल कोठारी सहित अशोक कुमार मेहता, करण मल जारौली, नवरत्न सिंह कोठारी, धीरज भाणावत, करण सिंह कटारिया, हेमन्त दक, किरण पोखरना, डॉ. प्रमिला जैन, वंदना जैन, सुमन कोठारी और अनीता गांधी आदि सदस्य मौजूद रहे। बैठक का समापन अल्पाहार के साथ हुआ।

सेवा पर्व के अंतर्गत विकसित भारत पर बनी पेंटिंग्स बनी आकर्षण का केन्द्र



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) के निर्देशानुसार पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर द्वारा 'विकसित भारत के रंग कला के संग' कार्यक्रम के तहत प्रोफेशनल आर्टिस्टों के लिए शनिवार को सुबह 9 बजे पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। शुक्रवार को विद्या भवन सीनियर सैकण्डरी स्कूल फतहपुरा में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के केन्द्र निदेशक फुरकान खान ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) के निर्देशानुसार विकसित भारत की थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता सेवा पर्व के रूप में पूरे देशभर में आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को शिल्पग्राम में प्रोफेशनल आर्टिस्टों के लिए सुबह 9 बजे पेंटिंग प्रतियोगिता की जाएगी। इस प्रतियोगिता में 30 वर्ष से अधिक के कोई भी कलाकार भाग ले सकते है। शुक्रवार को विद्या भवन सीनियर सैकण्डरी स्कूल फतहपुरा में विकसित भारत की थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें कई विद्यार्थियों ने विकसित भारत की कल्पना को सुंदर चित्रों में उकेरा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. आर.एल. सुमन, सुपरिंटेंडेट, महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर थे। साथ में केन्द्र के सहायक निदेशक वित्त एवं लेखा दुर्गेश चांदवानी, कार्यक्रम अधिशाषी हेमंत मेहता एवं स्कूल के प्राचार्य पुष्पेन्द्र सिंह राणावत उपस्थित थे। इसी कड़ी में आज दिनांक 27 सितम्बर को शिल्पग्राम में प्रोफेशनल आर्टिस्ट एवं मीरा गर्ल्स कॉलेज में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

उदयपुर में गूंजेगी सिंधियतः टाउन हॉल पर भव्य सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर शनिवार, 27 सितम्बर को सिंधी संस्कृति की रंगीनियों से सराबोर होगी। कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशन में राजस्थान सिंधी अकादमी, झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत और शहीद हेमू कालानी युवा मंच के संयुक्त तत्वावधान में शाम 6 बजे टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर भव्य सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्यसभा सांसद चन्नीलाल गरासिया, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवलरामानी, पूर्व राज्य मंत्री हरीश राजानी और झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष प्रतापराय चुग सहित अनेक जनप्रतिनिधि और विशिष्ट अतिथि शामिल रहेंगे। संयोजक राजेश खत्री ने बताया कि मंच पर अहमदाबाद की विजन सिंधु चिल्ड्रन अकादमी के 25 कलाकार अपनी आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। नृत्य, गीत-संगीत और रंगारंग प्रस्तुतियां सिंधी समाज की समृद्ध कला और परंपराओं की झलक पेश करेंगी। आयोजन में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। पास शहर के सभी सिंधी समाज भवनों पर उपलब्ध हैं। आयोजन समिति का कहना है कि यह अवसर नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने और समाज की एकता को मजबूत करने का काम करेगा। कल की शाम उदयपुर के लिए यादगार होगी ।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।